

वाणिज्यिक मोटर्स लिमिटेड

बनाम

व्यापार कर आयोग यू. पी., लखनऊ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 622-623/2015)

11 सितंबर, 2015

[दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, जे. जे.]

यू. पी व्यापार कर अधिनियम, 1948: धारा 21 (2), परंतुक जैसा कि 30.4.2001-निर्धारण वर्ष 1990-91 पर संशोधित किया गया है-क्या धारा 21 (2) के तहत 13.3.2002 पर जारी किया गया कारण बताएँ नोटिस, जिसमें निर्धारण वर्ष 1990-91 के संबंध में पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है, जिसमें निर्धारण 25.3.1995 पर पूरा किया गया था, वैध और कानून में स्वीकार्य है-आयोजित: धारा 21 (1) और पहले परंतुक के तहत सीमा के उद्देश्य के लिए, सीमा की अवधि को प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से गिना जाना है अर्थात् 31.3.1991-परंतुक को 30.4.2001 पर संशोधित किया गया था और पिछले प्रावधान जिसमें "ऐसे वर्ष के अंत से आठ वर्ष" शब्द शामिल थे, उनके स्थान पर "ऐसे वर्ष के अंत से छह वर्ष या 31 मार्च, 2002, जो भी बाद में हो" - द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था-संशोधन के आधार पर, मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन छह साल की

समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है और इसका मतलब यह नहीं होगा कि मूल्यांकन वर्ष की परवाह किए बिना 31.3.2002 द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि यह विधानमंडल के अपेक्षित इरादे के विपरीत होगा- इसलिए, पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत सीमा द्वारा बाधित होने के कारण मान्य नहीं थी। कर/कराधान: कानून की प्रयोज्यता-आयोजित: निर्धारण वर्ष में लागू कानून को तब तक लागू किया जाना है जब तक कि कोई संशोधन पूर्वव्यापी संचालन के साथ लागू न हो।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. हाथ में मौजूद मामले में 30.4.2001 पर संशोधित किए गए परंतुक और पिछले प्रावधान जिसमें "ऐसे वर्ष के अंत से आठ वर्ष" शब्द शामिल थे, को "ऐसे वर्ष के अंत से छह वर्ष या 31 मार्च, 2002, जो भी बाद में हो" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मूल मूल्यांकन आदेश दिनांकित 25.2.1995 है और पुनर्मूल्यांकन के लिए सूचना दिनांकित 13.3.2002 है। धारा 21 (1) और पहले परंतुक के तहत सीमा के उद्देश्य के लिए, सीमा की अवधि को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से गिना जाना है। इस प्रकार, 13.3.2002 दिनांकित सूचना छह वर्ष या मूल्यांकन वर्ष के अंत के आठ वर्ष से भी अधिक थी अर्थात् 1990-91। सवाल यह है कि क्या नोटिस को "ऐसे वर्ष के अंत से छह साल या 31 मार्च, 2002" अभिव्यक्ति द्वारा सहेजा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

नए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में छह साल की अवधि का पूरा प्रभाव होगा, जहां नोटिस जारी किया जाता है या परंतुक लागू होने की तारीख के बाद। [पैरा 16] (1053-ई-एच; 1054-ए-बी)

2. निर्धारण वर्ष में लागू कानून को तब तक लागू किया जाना है जब तक कि कोई संशोधन पूर्वव्यापी संचालन के साथ लागू न हो। राज्य विधानमंडल ने जानबूझकर इस अवधि को आठ साल से घटाकर छह साल कर दिया है। हालांकि, बाहरी सीमा या तो छह साल या 31 मार्च, 2002 तय की गई है। यह संशोधन न केवल निर्धारिती के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसका उद्देश्य राजस्व के हितों की रक्षा करना भी है। इस संशोधन से पहले, सीमा की अवधि आठ साल थी। ऐसे मामले हो सकते हैं जो नोटिस जारी करने के कारण लंबित थे क्योंकि पहले की सीमा अवधि पूर्व-संशोधित परंतुक के तहत आठ साल थी। परंतुक के बाद के भाग का इरादा इस तरह के लंबित आकलनों को सहेजना है और इसलिए एक विशिष्ट तिथि, यानी 31 मार्च, 2002 को शामिल किया गया है। अवधि को आठ वर्ष से घटाकर छह वर्ष करते हुए, 31.3.2002 द्वारा मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन को पूरा करने के लिए समय निर्दिष्ट किया गया है। यदि उक्त तिथि, अर्थात् आई. डी. 1, को बचत कारक के रूप में नहीं माना जाता, तो आठ साल की अवधि के लिए लंबित पुनर्मूल्यांकन मामले के दायरे में आ जाते और सीमा अवधि में कमी से राजस्व के ब्याज पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इसलिए, सुरक्षात्मक प्रावधान। यदि इस तरह का निर्माण नहीं किया जाता है, तो यह असमान होगा, एक तरह से असंगत होगा, क्योंकि एक तरफ सीमा की अवधि कम हो जाती है और एक निर्धारित तिथि तय करने से एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। विधायी उद्देश्य वित्तीय या मूल्यांकन वर्ष की परवाह किए बिना सीमा अवधि को बढ़ाना और बढ़ाना नहीं था। यदि राजस्व के रुख को स्वीकार किया जाना है, तो 2001 के संशोधन का प्रभाव वित्तीय वर्ष के संदर्भ के बिना मामलों को फिर से खोलने को सशक्त और अधिकृत करेगा, बशर्ते कि मूल्यांकन आदेश 31.3.2002 पर या उससे पहले किया गया हो। इस तरह की व्याख्या विधायी इरादे के विपरीत होगी क्योंकि उसी संशोधन ने सीमा अवधि को आठ साल से घटाकर छह साल कर दिया है। तार्किक परिणाम यह है कि विधायी इरादा सीमा अवधि को समाप्त करने और मिटाने का नहीं था, बल्कि "31 मार्च, 2002" की तारीख को केवल उन मामलों की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया था जिन्हें पहले आठ साल की सीमा अवधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार, 2001 का संशोधन पूरी तरह से पूर्वव्यापी नहीं है, लेकिन यह आंशिक रूप से पूर्वव्यापी है। यह सीमा अवधि को आठ वर्ष से घटाकर छह वर्ष कर देता है और साथ ही आठ वर्ष और छह वर्ष के भीतर मामलों के संबंध में राजस्व के हित की रक्षा और सुरक्षा करता है बशर्ते कि पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च, 2002 तक पूरा हो जाए। [पैरा 19] [1057-डी-एच; 1058-ए-एफ]

सीटीओ बनाम विश्वनाथ झुनझुनवाला 1996 (5) पूरक। एससीआर 286: (1996) 5 एससीसी 626; अहमदाबाद

मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड बनाम एस. जी. मेहता, आई. टी. ओ. ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1436:1963 सप्लीमेंटरी एस. सी. आर. 92; राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ 2003 (3) एस. सी. आर.

1: (2003) 5 एस. सी. सी. 23; तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 2011 (4) एस. सी. आर. 838: (2011) 6 धारा 739-पर निर्भर था।

अतिरिक्त आयुक्त (कानूनी) और अन्य बनाम ज्योति ट्रेडर्स और अन्य 1998 (3) पूरक एस. सी. आर. 67: (1999) 2 धारा 77-विशिष्ट।

अतिरिक्त आयुक्त (कानूनी) और एएनआर बनाम ज्योति ट्रेडर्स और अन्य 1998 (3) पूरक एस. सी. आर. 67: (1999) 2 एस. सी. सी. 77; बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त जे. टी. 2007 (5) एस. सी. 311; अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड बनाम एस. जी. मेहता, आई. टी. ओ. ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1436:1963 सप्लीमेंट एस. सी. आर. 92; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल कुमार रमेश चंद्र ग्लास वर्क्स (2005) 11 एस. सी. सी. 451; उड़ीसा राज्य बनाम संग्राम केशरी मिश्रा (2010) 13 एस. सी.

सी. 311; रक्षा मंत्रालय बनाम प्रभाष चंद्र मिर्धा 2012 (6) एस. सी. आर.  
182: (2012) 11 धारा 565-संदर्भित।

### मामला विधि संदर्भ

1998 (3) पूरक एस. सी. आर. 67 विभेधात्मक अनुच्छेद 6,16

जे. टी. 2007 (5) एस. सी. 311 निर्दिष्ट पैरा 6

1963 पूरक एस. सी. आर. 92 पर भरोसा किया अनुच्छेद 6,16

(2005) 11 एस. सी. सी. 451 निर्दिष्ट पैरा 11

(2010) 13 एस. सी. सी. 311 निर्दिष्ट पैरा 11

2012 (6) एस. सी. आर. 182 निर्दिष्ट पैरा 11

1996 (5) पूरक एस. सी. आर. 286 पर भरोसा किया पैरा 12,16

2003 (3) एस. सी. आर. 1 पर निर्भर था पैरा 17

2011 (4) एस. सी. आर. 838 पर निर्भर था पैरा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2015 की सिविल अपील संख्या 622-  
623

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.03.2014 से, 2002 की डबल्यू. पी. संख्या 1513 में लखनऊ पीठ और 2014 की आर. पी. संख्या 365 में 25.04.2014।

अपीलार्थी की ओर से पवनश्री अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल।

प्रत्यर्थियों के लिए रवि प्रकाश मेहरोत्रा और राजीव दुबे।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे. द्वारा दिया गया-

1. अपीलार्थी यू. पी. व्यापार कर अधिनियम, 1948 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') के तहत एक पंजीकृत विक्रेता है और मैसर्स बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा निर्मित स्कूटरों से निपटने के लिए अधिकृत है। और मूल्यांकन वर्ष 1990-91 के दौरान, यू. पी. सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम के साथ-साथ स्टोर विभाग की कैंटीन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को रुपये 5,23,93,337.57 की राशि में दोपहिया वाहन बेचे थे। मूल्यांकन के दौरान, अपीलार्थी ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे जो दिनांक 31.1.1985 की छूट अधिसूचना संख्या 7037 के संदर्भ में छूट का दावा करने के लिए जारी किए जाने की आवश्यकता थी। निर्धारिती ने 270 बिक्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे और उसी के आधार पर उसे निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.3.1995 के मूल्यांकन आदेश के माध्यम से उपरोक्त राशि के लिए स्कूटरों की बिक्री पर छूट दी गई थी। जैसा कि

राजस्व द्वारा दावा किया गया है, बाद के चरण में यह पता चला कि विचाराधीन स्कूटरों की कुल बिक्री राशि वास्तव में रु. 5,23,93,337.57 के बजाय रु. 4,26,94,276.59 थी और इसलिए निर्धारिती Rs.97,02,050.65 की सीमा तक स्कूटरों की बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जिस पर उसे पहले 16.4.1994 के परिपत्र को देखते हुए बिक्री कर छूट दी गई थी।

2. मूल निर्धारण को दोषपूर्ण मानते हुए, अपीलार्थी को 13.3.2002 दिनांकित एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 18.3.2002 की तारीख तय की गई थी, जिसमें निर्धारिती को यह स्पष्टीकरण देने के लिए कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए और कर घटक का एहसास नहीं किया जाना चाहिए।

3. निर्धारिती ने दो आधारों को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दाखिल किया, अर्थात्: (i) अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि इसे निर्धारण वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह साल के अंतराल के बाद शुरू की जा रही सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, यानी अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा 2 के परंतुक के आलोक में और (ii) निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान लेखा पुस्तकों की जांच की गई थी जो वर्ष के

मूल्यांकन आदेश से प्रकट होती है और इसलिए, मूल मूल्यांकन करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले से ही विचार की गई सामग्री के कारण, मूल्यांकन को फिर से शुरू करने के लिए कदम जारी नहीं किए जा सके।

4. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने वाले सक्षम प्राधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्धारिती को दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता थी। उस समय, अपीलार्थी ने 2002 की रिट याचिका संख्या 1513 को प्राथमिकता दी और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया, नोटिस जारी किया और एक अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया कि मूल्यांकन कार्यवाही जारी रह सकती है लेकिन कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

5. जवाब में उठाई गई दलीलों को रिट याचिका में आगे बढ़ाया गया था और विभाग द्वारा जवाबी हलफनामा दायर करके उनका विरोध किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 21 (2) में शामिल संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव है और मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए उठाए गए कदम समय के भीतर थे और रिट क्षेत्राधिकार के आह्वान के लिए कोई औचित्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान देने के बाद निर्धारण के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए: - "1. क्या ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों

में अधिनियम के तहत एक पूर्ण मूल्यांकन निर्धारित अवधि के बाद फिर से खोला जा सकता है जब उस अवधि को कानून में संशोधन करके बढ़ाया गया है? क्या धारा 21 (1) के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने का कोई मामला बनाया गया है और क्या यह राय बदलने का मामला है?

6. जहां तक पहले मुद्दे का संबंध है, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त आयुक्त (कानूनी) और एक अन्य बनाम ज्योति ट्रेडर्स और एक अन्य मामले में विस्तार से, बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक करों के सहायक आयुक्त में निर्णय और उसमें निर्दिष्ट निर्णय यानी अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कंपनी को संदर्भित किया। लिमिटेड बनाम एस. जी. मेहता, आई. टी. ओ. 3, और इस प्रकार राय दी: - "अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत इसके संशोधन से पहले, मूल्यांकन प्राधिकरण, विक्रेता को नोटिस जारी करने और ऐसी जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे, कानून के अनुसार विक्रेता का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया है कि इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कोई आदेश ऐसे वर्ष के अंत से 2 वर्ष की समाप्ति के बाद या 31.3.1988 तक, जो भी बाद में हो, नहीं किया जाएगा। हालांकि, संशोधन के बाद, उप-धारा (2) में एक परंतुक जोड़ा गया था, जिसके तहत बिक्री कर आयुक्त मूल्यांकन प्राधिकरण को उपरोक्त अवधि

की समाप्ति के बाद मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन ऐसे वर्ष के अंत से 8 साल बाद नहीं, इसके बावजूद कि इस तरह के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में राय में बदलाव शामिल हो सकता है। यह परंतुक दिनांक 19 फरवरी, 1991 से लागू हुआ। इस परंतुक को और संशोधित किया गया और "ऐसे वर्ष के अंत से छह साल या 31 मार्च, 2002 जो भी बाद में हो" को "ऐसे वर्ष से आठ साल" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। द्वितीय परंतुक को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987-88 के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन 31 तक किया जा सकता है। 31.3.1993 और चौथे परंतुक के अनुसार वर्ष 1989-90 के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन 31.3.1995 तक किया जा सकता है। हमें नहीं लगता कि उप-धारा (2) और इसमें जोड़ा गया परंतुक किसी को भी संदेह में छोड़ता है कि जिस तारीख को संशोधित परंतुक लागू हुआ था, उस तारीख को बिक्री कर आयुक्त ऐसे वर्ष से छह साल की समाप्ति के बाद, यानी 31.3.1999 या 31 मार्च, 2002, जो भी बाद में हो, मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने को अधिकृत कर सकता है। यदि उक्त परंतुक को जोड़ने से पहले धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की अवधि समाप्त हो गई थी, तो यह मायने नहीं रखता है। जैसा भी हो, इन प्रावधानों का मतलब होगा कि वर्ष 1987-88 के लिए मूल्यांकन 31 मार्च, 1993 तक फिर से खोला जा सकता है। बिक्री कर आयुक्त द्वारा प्राधिकरण और धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत

मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन को पूरा करना विशेष मूल्यांकन वर्ष के 6 वर्षों के भीतर या 31.3.2002 तक, जो भी बाद वाला हो, पूरा करना होगा। निर्धारिती को सूचना बिक्री कर आयुक्त द्वारा प्राधिकरण का पालन करती है। यह विवादित नहीं है कि एक राजकोषीय कानून का पूर्वव्यापी संचालन हो सकता है। यदि हम प्रत्यर्थियों द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करते हैं, तो अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में जोड़ा गया परंतुक जो 31.3.2002 तक की सीमा प्रदान करता है, निरर्थक हो जाता है। अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में अब जोड़ा गया परंतुक बिक्री कर आयुक्त पर मूल्यांकन को फिर से नहीं खोलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है यदि अवधि, जैसा कि पहले निर्धारित किया गया था, परंतुक के लागू होने से पहले समाप्त हो गई थी।

7. ऐसा कहने के बाद उच्च न्यायालय ने प्रावधान को लागू करने में विधायिका के इरादे को समझने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया और उस संदर्भ में उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 21 (2) के परंतुक के प्रारंभ की तारीख इसके पूर्वव्यापी संचालन को नियंत्रित नहीं करती है; कि अधिनियम की धारा 21 (2) के परंतुक के प्रतिस्थापन के बाद संशोधन के बाद, यह विशेष मूल्यांकन वर्ष के छह साल या 31.3.2002 तक जो भी बाद में हो; और परंतुक को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा निर्धारिती को जारी किया गया नोटिस समय के भीतर था। डिवीजन बेंच ने

मेसर्स प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स और अन्य बनाम व्यापार कर के अतिरिक्त आयुक्त और अन्य मामले में दिए गए एक अन्य डिवीजन बेंच के फैसले को इस आधार पर घोषित किया कि उसने संशोधित प्रावधान और ज्योति ट्रेडर्स (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले पर ध्यान नहीं दिया था।

8. सीमा के मुद्दे का जवाब देने के बाद, उच्च न्यायालय दूसरे प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा और उस संदर्भ में यह माना गया कि मूल मूल्यांकन आदेश पारित करते समय प्रारंभिक राय यह थी कि स्कूटरों की बिक्री पर छूट देने के लिए नोटिस जारी करते समय बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन राजस्व ने पाया था कि गलत तरीके से 500 करोड़ रुपये की सीमा तक छूट दी गई थी। 97, 02, 050.65 जिस पर कर लगाया जाना चाहिए था और तदनुसार दूसरे आधार पर कोई सार नहीं मिला। इस दृष्टिकोण के कारण, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील।

9. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री पवनश्री अग्रवाल और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा को सुना है।

10. विवाद की सराहना करने के लिए धारा 21 (2) को संशोधित रूप में पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करना उचित है।

धारा 21-वर्ष के दौरान निर्धारित न किए गए कारोबार पर कर का निर्धारण (2) इस धारा में अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश ऐसे वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के बाद या 31 मार्च, 1998, जो भी बाद में हो, नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि आयुक्त, अपने दम पर या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर, संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा करना न्यायसंगत और समीचीन है, तो उस ओर से निर्धारण प्राधिकरण को अधिकृत करता है, तो ऐसा मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद किया जा सकता है, लेकिन [ऐसे वर्ष के अंत से छह साल या 31 मार्च, 2002 की समाप्ति के बाद नहीं। जो भी बाद में हो] इसके बावजूद कि ऐसे मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में राय में परिवर्तन शामिल हो सकता है:

बशर्ते कि मूल्यांकन वर्ष 1987-88 के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च, 1993 तक किया जा सकता है: बशर्ते कि यदि धारा 4-ए के तहत दिए गए पात्रता प्रमाण पत्र को धारा 4-ए की उप-धारा (3) के तहत आयुक्त द्वारा संशोधित या रद्द कर दिया गया है, तो मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का आदेश उपरोक्त प्रमाण पत्र में संशोधन या

रद्द करने वाले आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक साल के भीतर या 31 मार्च, 1995 तक, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है। बशर्ते कि मूल्यांकन वर्ष 1989-90 के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च, 1995 तक किया जा सकता है।

11. उपरोक्त संशोधित प्रावधान की रचना के संबंध में, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत जारी किया गया कारण बताएँ नोटिस, जिसमें निर्धारण वर्ष 1990-91 के संबंध में निर्धारिती का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई है, जिसमें मूल्यांकन 25.3.95 पर पूरा किया गया था, वैध और कानून में स्वीकार्य है। निर्धारिती-अपीलार्थी का रुख यह है कि इसके तहत मूल्यांकन को फिर से खोलना केवल 31.3.1997 तक ही हो सकता है, यानी मूल्यांकन वर्ष 1991 के अंत से छह साल की अवधि और इसलिए, 13.3.2002 पर जारी किया गया नोटिस कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। राजस्व की स्थिति यह है कि धारा 21 (2) के तहत नियोजित भाषा के अनुसार, मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या तो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के अंत से छह साल के भीतर या 31.3.2002 तक जो भी बाद में हो, किया जा सकता है, इसलिए, सूचना मान्य है और सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि संशोधन के आधार पर, मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन छह साल की समाप्ति के बाद नहीं

किया जा सकता है और इसका मतलब यह नहीं होगा कि मूल्यांकन वर्ष की परवाह किए बिना 31 मार्च, 2002 तक मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि यह विधानमंडल के अपेक्षित इरादे के विपरीत होगा। राजस्व के लिए विद्वान वकील, इसके विपरीत, तर्क देंगे कि सीमा को मूल्यांकन वर्ष 1991 या 31.3.2002 से छह साल की अवधि तक बढ़ा दिया गया है या जो भी बाद में हो, और इसलिए, ज्योति ट्रेडर्स (उपरोक्त) में घोषणा पूरी तरह से लागू होगी क्योंकि पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस निर्धारित अवधि के भीतर भेजा गया है, अर्थात् 31.3.2002 क्योंकि मूल मूल्यांकन में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं जो दोषपूर्ण पाई गई थीं। इसके अलावा, एक तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिल कुमार रमेश चंद्र ग्लास वर्क्स, उड़ीसा राज्य बनाम संग्राम केशरी मिश्रा और रक्षा मंत्रालय बनाम प्रभाष चंद्र मिर्धा में दिए गए निर्णयों को देखते हुए रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताने के लिए एक नोटिस में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

12. सबसे पहले, हम ज्योति प्रयोगशाला (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख करेंगे। उक्त मामले में, अधिनियम के तहत मूल्यांकन वर्ष 1985-86 के संबंध में मूल्यांकन 27.11.1989 पर पूरा किया गया था और ज्योति व्यापारियों के संबंध में, उक्त वर्ष के लिए मूल्यांकन 28.2.1990 पर पूरा किया गया था। निर्धारण वर्ष 1985-86 के लिए अधिनियम की

धारा 21 के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की अवधि जो चार साल थी, निर्धारिती ज्योति व्यापारियों के संबंध में 31.3.1990 पर समाप्त हो गई। अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि संशोधन अधिनियम को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सहमति मिली थी और संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लागू होने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई थीं। अधिनियम की धारा 21 जिसमें एक संशोधन किया गया था और न्यायालय उस प्रासंगिक प्रावधान से संबंधित था जो 19.2.1991 से लागू हुआ था। संशोधन के आधार पर, बिक्री कर अधिकारी ने बिक्री कर आयुक्त से मंजूरी लेने के बाद, निर्धारिती को पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी किए। मंजूरी देने और पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने के आदेशों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और रिट अदालत ने इसे रद्द कर दिया। इस न्यायालय ने धारा 21 की उप-धारा 2 के प्रावधान पर ध्यान दिया जैसा कि संशोधन अधिनियम 1981 द्वारा जोड़ा गया था जो 19.2.1991 से लागू हुआ था। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब अधिनियम की धारा 21 के तहत वर्ष के लिए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की अवधि उसकी उप-धारा 2 में परंतुक डालने से पहले समाप्त हो गई थी, तो संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस न्यायालय के समक्ष राजस्व का रुख यह था कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21 की उप धारा 2 पर दी गई व्याख्या, यदि स्वीकार की जाती है, तो प्रावधान को संभावित प्रकृति का बना देगा जो परंतुक को निरर्थक बना

देगा। यह भी तर्क दिया गया कि परंतुक वास्तव में उप-धारा के तहत निर्धारित चार साल की अवधि की समाप्ति के बाद संचालित होता है और नोटिस का पालन आयुक्त से आदेश प्राप्त करने के बाद करना होता है न कि उससे पहले। सीटीओ बनाम विश्वनाथ झुनझुनवाला में प्राधिकारी पर विश्वास दिया गया था।

13. विश्वनाथ झुनझुनवाला (उपरोक्त) में निर्णय बंगाल वित्त (बिक्री कर) (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 से संबंधित था, जिसने मूल अधिनियम की धारा 26 (1) को प्रतिस्थापित किया, जिसने राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संभावित या पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियम बनाने का अधिकार दिया। उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बंगाल बिक्री कर नियम, 1941 के नियम 80 (5) में संशोधन किया गया। संशोधित नियम में प्रावधान किया गया है कि आयुक्त या कोई अन्य प्राधिकरण जिसे शक्ति सौंपी गई है, वह अपने स्वयं के प्रस्ताव से अधिनियम या उसके तहत पारित किसी भी मूल्यांकन या आदेश को संशोधित नहीं करेगा, यदि मूल्यांकन किया गया था या आदेश छह साल से अधिक समय पहले पारित किया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस जारी किए जाने पर, उच्च न्यायालय को इसे रद्द करने के लिए स्थानांतरित किया गया था और इसने फैसला सुनाया कि नियम के संशोधन द्वारा, जो मूल्यांकन पूरा हो चुका था, उसे इस तरह के पूरा होने की तारीख के छह

साल के भीतर संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जब नियम के अपरिवर्तित प्रावधान के तहत मूल्यांकन को संशोधित करने का अधिकार संशोधन की तारीख पर वर्जित था, तो इस तरह के मूल्यांकन को फिर से या संशोधित नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी राय दी गई थी कि संशोधित अधिसूचना न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ से मूल्यांकन के संशोधन की कोई शक्ति प्रदान करती है जो उस तारीख को वर्जित थी जिस दिन इसे जारी किया गया था। इस न्यायालय ने आई. टी. ओ. बनाम एस. के. हबीबुल्ला, एस. एस. गाडगिल, आई. टी. ओ. बनाम लाल एंड कंपनी और आई. टी. ओ. बनाम एल. एन. डी. प्रसाद देवशंकर भट्ट में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार राय दी:

"12. इसलिए, हमें उक्त अधिसूचना का स्पष्ट अर्थ खोजना होगा। यदि अर्थ के बारे में कोई संदेह नहीं है, तो उक्त अधिसूचना द्वारा लाए गए संशोधन को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। यदि भाषा स्पष्ट रूप से ऐसा कहती है या स्पष्ट रूप से इंगित करती है, तो पूर्वव्यापीता 1-11-1971 से प्रभाव के साथ दी जानी चाहिए, ताकि छह साल की अवधि के भीतर किए गए सभी आकलनों को शामिल किया जा सके, चाहे वे चार साल की अवधि की समाप्ति के कारण अंतिम हो गए हों या नहीं।

13. उक्त अधिसूचना के कारण, नियम 80 (5) (इसे) को आयुक्त (या अन्य प्राधिकारी जिसे आयुक्त द्वारा इस संबंध में शक्ति सौंपी गई है) को अधिनियम या नियमों के तहत पारित किसी भी मूल्यांकन या आदेश को संशोधित करने से रोकने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यदि मूल्यांकन किया गया है या आदेश 1-11-1971 से छह साल पहले पारित किया गया है। इसके विपरीत, नियम 80 (5) (ii) आयुक्त (या अन्य प्राधिकारी) को अधिनियम या नियमों के तहत पारित किसी भी मूल्यांकन या आदेश को अपने स्वयं के प्रस्ताव को संशोधित करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि मूल्यांकन नहीं किया गया हो या आदेश छह साल से अधिक पहले पारित नहीं किया गया हो। यह स्पष्ट अर्थ होने के कारण, उक्त अधिसूचना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। पूर्ण प्रभाव तभी दिया जा सकता है जब उक्त अधिसूचना को न केवल उन आकलनों पर लागू होने के रूप में पढ़ा जाए जो अधूरे थे, बल्कि उन आकलनों पर भी लागू किया जाता है जो पहले निर्धारित चार साल की अवधि बीत जाने के कारण अंतिम रूप से पहुंच गए थे। जहां इस तरह की असंदिग्ध भाषा का उपयोग किया जाता है, यह माना जाना चाहिए कि विधायिका का इरादा संशोधित प्रावधान को उन आकलनों पर भी लागू करना था जो इस तरह से अंतिम हो गए थे; यदि इरादा अन्यथा था, तो विधायिका ने ऐसा कहा होगा।"

14. इसके बाद इस न्यायालय ने कई अन्य निर्णयों का उल्लेख किया और अंततः धारा 21 में संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा:-"अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड और विश्वनाथ झुनझुनवाला के मामलों में दो निर्णय हमारे सामने वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे के अधिक करीब हैं। उन्होंने निर्धारित किया कि यह प्रावधान की भाषा है जो मायने रखती है और जब अर्थ स्पष्ट होता है, तो इसे पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। इन दोनों मामलों में, इस न्यायालय ने माना कि मौजूदा प्रावधान में संशोधन करने वाले परंतुक ने इसे पूर्वव्यापीता दी है। जब कानून का प्रावधान स्पष्ट होता है, तो इसे पूरी तरह से संचालित करना पड़ता है और इसके संचालन की कोई सीमा नहीं हो सकती है। विश्वनाथ झुनझुनवाला मामले में इस अदालत ने कहा कि यदि भाषा स्पष्ट रूप से ऐसा कहती है या स्पष्ट रूप से इंगित करती है, तो प्रावधान को पूर्वव्यापीता दी जानी चाहिए। आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34 के तहत, यह नोटिस की सेवा है जो अनिवार्य है। मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए अपरिहार्य आवश्यकता, जहां आय मूल्यांकन से बच गई थी। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। इसके संशोधन से पहले अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत, मूल्यांकन प्राधिकरण, विक्रेता को नोटिस जारी करने और ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, कानून के अनुसार विक्रेता का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया है कि

इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कोई आदेश ऐसे वर्ष के अंत से 4 वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा। हालांकि, संशोधन के बाद, उप-धारा (2) में एक परंतुक जोड़ा गया था, जिसके तहत बिक्री कर आयुक्त मूल्यांकन प्राधिकरण को ऐसे वर्ष के अंत से 8 साल की समाप्ति से पहले मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत करता है, इसके बावजूद कि इस तरह के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन में राय में बदलाव शामिल हो सकता है। यह परंतुक 19-2-1991 से लागू हुआ। हमें नहीं लगता कि उप-धारा (2) और इसमें जोड़ा गया परंतुक किसी को भी संदेह में छोड़ता है कि उस तारीख को जब परंतुक लागू हुआ था, बिक्री कर आयुक्त उस विशेष निर्धारण वर्ष के अंत से 8 साल की समाप्ति से पहले मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने को अधिकृत कर सकता है। यदि उक्त परंतुक को जोड़ने से पहले धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की अवधि समाप्त हो गई थी तो यह मायने नहीं रखता है: यहां, यह धारा 21 के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन का पूरा होना है जो उस विशेष मूल्यांकन वर्ष के 8 वर्षों की समाप्ति से पहले किया जाना है। जैसा भी है, इन प्रावधानों का मतलब होगा कि वर्ष 1985-86 के लिए मूल्यांकन को 31-3-1994 तक फिर से खोला जा सकता है। बिक्री कर आयुक्त द्वारा प्राधिकरण और धारा 21 की उप-धारा (1) के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन को विशेष मूल्यांकन वर्ष के 8 वर्षों के भीतर पूरा करना होगा।

और पुनः- "यदि हम प्रत्यर्थियों द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करते हैं, तो अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में जोड़ा गया परंतुक निरर्थक हो जाता है। अधिनियम की शुरुआत अधिनियम के संचालन से अलग हो सकती है, हालांकि कभी-कभी दोनों समान हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) में अब जोड़ा गया परंतुक बिक्री कर आयुक्त पर मूल्यांकन को फिर से नहीं खोलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, यदि अवधि, जैसा कि पहले निर्धारित की गई थी, परंतुक के लागू होने से पहले समाप्त हो गई थी। प्रावधान की भाषा देखनी होगी। यदि यह स्पष्ट है, तो इसका पूरा प्रभाव देना होगा। स्वयं को आश्वस्त करने के लिए, इस तरह के प्रावधान को लागू करने में विधायिका के इरादे पर विचार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 21 (2) के परंतुक के प्रारंभ की तारीख इसके पूर्वव्यापी संचालन को नियंत्रित नहीं करती है। पहले मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन उस विशेष मूल्यांकन वर्ष के चार वर्षों के भीतर पूरा किया जा सकता था और अब संशोधन द्वारा अधिनियम की धारा 21 (2) में परंतुक को जोड़कर यह आठ वर्ष है। एकमात्र सुरक्षा यह है कि यह बिक्री कर आयुक्त की संतुष्टि के बाद है। परंतुक 19-2-1991 से लागू होता है और परंतुक को केवल पढ़ने से पता चलता है कि इस परंतुक का संचालन पिछले आठ मूल्यांकन वर्षों से संबंधित है और इसमें शामिल है।

15. यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय द्वारा धारा 21 की उप-धारा (2) में संशोधन पर संशोधन प्रावधान द्वारा व्याख्या की गई थी जो 19.2.1991 से लागू हुआ था। न्यायालय ने विश्वनाथ झुनझुनवाला (ऊपर) में प्राधिकरण पर भरोसा किया, जैसा कि न्यायालय ने सोचा था, एक निकटवर्ती निर्णय था। इससे पहले के मामले में नियम 80 (5) (ii) की व्याख्या व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करने के लिए की गई थी और स्पष्ट रूप से यह निहितार्थ था कि अधिसूचना को पूर्वव्यापीता दी जानी चाहिए ताकि इसका पूरा प्रभाव हो सके। अदालत ने राय दी कि संशोधन पर स्पष्ट अर्थ रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से "मूल्यांकन किया गया है या आदेश छह साल से अधिक समय पहले पारित किया गया है", और पूर्ण प्रभाव केवल तभी दिया जा सकता है जब उक्त अधिसूचना को इस तरह पढ़ा जाए कि यह न केवल उन आकलनों पर लागू होता है जो अधूरे थे, बल्कि उन आकलनों पर भी लागू होता है जो पहले निर्धारित चार साल की अवधि बीत जाने के कारण अंतिम रूप से पहुंच गए थे। न्यायालय ने आगे कहा कि जहां भाषा नियम 80 (5) (ii) के रूप में असंदिग्ध थी, यह माना जाना चाहिए कि विधायिका का इरादा संशोधित प्रावधान को उन आकलनों पर भी लागू करना था जो अंतिम हो गए थे, क्योंकि यदि इरादा अन्यथा होता, तो विधायिका ने ऐसा कहा होता। असंदिग्ध थी, यह माना जाना चाहिए कि विधायिका का इरादा संशोधित प्रावधान को उन आकलनों पर

भी लागू करना था जो अंतिम हो गए थे, क्योंकि यदि इरादा अन्यथा होता, तो विधायिका ने ऐसा कहा होता।

16. हाथ में मौजूद मामले में 30.4.2001 पर संशोधित किए गए परंतुक और पिछले प्रावधान जिसमें "ऐसे वर्ष के अंत से आठ वर्ष" शब्द शामिल थे, को "ऐसे वर्ष के अंत से छह वर्ष या 31 मार्च, 2002, जो भी बाद में हो" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष 1990-91 या वर्ष समाप्त होने वाला 31.3.1991 है। मूल मूल्यांकन आदेश दिनांकित 25.2.1995 है और पुनर्मूल्यांकन के लिए सूचना दिनांकित 13.3.2002 है। धारा 21 (1) और पहले परंतुक के तहत सीमा के उद्देश्य के लिए, सीमा की अवधि को संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से गिना जाना है। इस प्रकार, 13.3.2002 दिनांकित सूचना छह वर्ष या मूल्यांकन वर्ष के अंत के आठ वर्ष से भी अधिक थी अर्थात् 1990-91। सवाल यह है कि क्या नोटिस को "ऐसे वर्ष के अंत से छह साल या 31 मार्च, 2002" अभिव्यक्ति द्वारा सहेजा जाता है। ज्योति ट्रेडर्स (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात की पृष्ठभूमि में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि नए मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में छह साल की अवधि का पूरा प्रभाव होगा, जहां नोटिस जारी किया जाता है या परंतुक लागू होने की तारीख के बाद। यह ध्यान में रखना होगा कि सीमा कानून जब किसी पक्ष के महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावित करता है,

तो इस तरह के बाद के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से तब तक नहीं पढ़ा जाना चाहिए जब तक कि संशोधन इस तरह से आवश्यक निहितार्थ द्वारा निर्धारित या आवश्यक न हो। यह विश्वनाथ झुनझुनवाला (उपरोक्त) में आयोजित किया गया है जब विधायिका का इरादा स्पष्ट हो और भाषा स्पष्ट हो या यह निहित रूप से अनुसरण करती है, तो पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और प्रावधान को पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए। इस संबंध में, अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में एक संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ उपयुक्त होगा। बहुमत का दृष्टिकोण, जैसा कि स्पष्ट है, निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

"विधायिका उन कानूनों को लागू करके पर्याप्त अधिकारों को प्रभावित कर सकती है जो स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी हैं या ऐसी भाषा का उपयोग करके जिसका वह आवश्यक परिणाम हो। और यह भाषा एक अधिनियम को प्रारंभिक खंड के किसी भी प्रावधान की तुलना में अधिक पूर्वव्यापीता दे सकती है। जब ऐसा होता है तो इस प्रकार पूर्वव्यापी, स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से बनाए गए प्रावधान, प्रारंभ की तारीख से पहले की तारीख से संचालित होते हैं और अधिकारों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस तरह के संचालन के लिए, बिना किसी बाधा के जारी रहते हैं।"

17. इस संदर्भ में, राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक अंश पुनः

प्रस्तुत करने योग्य है:-"कि किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। प्रत्येक विधान, चाहे वह संभावित हो या पूर्वव्यापी, विधायी क्षमता के प्रश्न के अधीन होना चाहिए। पूर्वव्यापी निर्णय कुछ कसौटी पर लिया जा सकता है जैसे कि: (1) उपयोग किए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन प्रदान करना चाहिए या स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी संचालन का संकेत देना चाहिए; (ii) पूर्वव्यापीता उचित होनी चाहिए और अत्यधिक या कठोर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह असंवैधानिक के रूप में खारिज होने का जोखिम उठाती है; (iii) जहां न्यायिक निर्णय को दूर करने के लिए कानून पेश किया जाता है, निर्णय के वैधानिक आधार को हटाए बिना निर्णय को नष्ट करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी अधिनियम को पूर्वव्यापीता देने के लिए विधायी इरादे की अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं है। एक मूल वैधानिक परिवर्तन के साथ एक मान्य खंड केवल उन तरीकों में से एक है जो अपरिवर्तित कानून के तहत कार्यों को अस्थिर, निर्बाध छोड़ देते हैं। नतीजतन, एक मान्य खंड की अनुपस्थिति अपने आप में वैधानिक प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, अगर ऐसी पूर्वव्यापीता अन्यथा स्पष्ट है।

18. तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ में, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:-"इसलिए सीमा प्रावधान तथ्यों के एक

समूह के संदर्भ में प्रक्रियात्मक हो सकते हैं लेकिन तथ्यों के विभिन्न समूह के संदर्भ में ठोस हो सकते हैं क्योंकि अधिकार दोनों पक्षों को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, परीक्षण यह देखने के लिए है कि क्या कानून, यदि किसी विशेष प्रकार के मामले में पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाता है, तो मौजूदा अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करेगा। समय सीमा का अभिवचन करने का अर्जित अधिकार, जो सांविधिक अवधि समाप्त होने के बाद अर्जित किया जाता है, फिर भी एक अधिकार है, भले ही यह एक ऐसे अधिनियम के तहत उत्पन्न होता है जो प्रक्रियात्मक है और एक ऐसा अधिकार है जिसे पूर्वव्यापी संचालन का अभिवचन करते हुए तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि एक विपरीत इरादा कानून से स्पष्ट न हो। इसलिए, जब तक भाषा स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ से प्रकट नहीं होती है, तब तक निहित अधिकारों को विभाजित करने वाले कानून के विपरीत इरादे को संभावित माना जाना चाहिए।

19. कानून के उपरोक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या "ऐसे वर्ष के अंत से छह साल या 31 मार्च, 2002, जो भी बाद में हो" शब्दों का संशोधन और परिचय या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से पूर्वव्यापी माना जा सकता है। मुख्य सिद्धांत जो स्वीकार किया जाता है वह यह है कि मूल्यांकन वर्ष में लागू कानून को तब तक लागू किया जाना है जब तक कि कोई संशोधन पूर्वव्यापी संचालन

के साथ लागू न हो। तत्काल मामले में, विधानमंडल ने अवधि को आठ साल से घटाकर छह साल करके संशोधन लाया है। परंतुक में प्रयुक्त भाषा की सावधानीपूर्वक जांच और सराहना की जानी चाहिए। ज्योति ट्रेडर्स (ऊपर) में, न्यायालय उस संशोधन पर विचार कर रहा था जिसमें "ऐसे वर्ष के अंत से आठ वर्षों में" लाए गए शब्दों की व्याख्या की गई थी और न्यायालय ने राय दी थी कि इरादे को पूरा प्रभाव देने के लिए, इसे आठ साल के पिछले मूल्यांकन तक वापस जाना होगा। वर्तमान संशोधन में, जो शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं, वे हैं "ऐसे वर्ष के अंत से छह साल या 31 मार्च, 2002, जो भी बाद में हो"। हम पहले ही कह चुके हैं कि छह साल की अवधि को पूरी तरह से लागू किया जाना है। इसमें संदेह का कोई निशान नहीं हो सकता है। "या 31 मार्च, 2002, जो भी बाद में हो" शब्दों का बहुत महत्व है। इस तिथि को निर्दिष्ट करने के लिए विधायिका के इरादे को समझना बेहद महत्वपूर्ण है, जब सीमा अवधि को आठ साल से घटाकर छह साल कर दिया गया था। राजस्व के लिए विद्वान वकील का यह निवेदन है कि संशोधित परंतुक बिक्री कर आयुक्त पर मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, भले ही आठ या छह साल की संशोधन से पहले या बाद की अवधि के तहत परंतुक लागू होने से पहले सीमा समाप्त हो गई हो और उच्च न्यायालय का यह मानना उचित है कि मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या तो विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के अंत से छह साल के भीतर या जो भी बाद में हो, किया जा सकता है।

पहली बार में, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या, जिसे राज्य के विद्वान वकील द्वारा दृढ़ता से समर्थित किया गया है, आकर्षक लग सकती है, लेकिन बारीकी से जांच करने पर, व्याख्या में भ्रान्ति स्पष्ट हो जाती है। जहाँ तक छह वर्षों का संबंध है, जैसा कि पहले कहा गया है, कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। राज्य विधानमंडल ने जानबूझकर इस अवधि को आठ साल से घटाकर छह साल कर दिया है। इस तरह की अवधि में कमी निश्चित रूप से निर्धारिती के लिए फायदेमंद है। यह ध्यान देने योग्य है कि अवधि को घटाकर छह साल कर दिया गया था, हालांकि, उपयोग की गई भाषा में, बाहरी सीमा या तो छह साल या 31 मार्च, 2002 तय की गई है और इसलिए, परंतुक के बाद के भाग में भी 31 मार्च, 2002 की तारीख निर्दिष्ट की गई है। जैसा कि हम समझते हैं, यह संशोधन न केवल निर्धारिती के लिए फायदेमंद है, बल्कि राजस्व के हितों की रक्षा करने का भी इरादा रखता है। इस संशोधन से पहले, सीमा की अवधि आठ साल थी। ऐसे मामले हो सकते हैं जो नोटिस जारी करने के कारण लंबित थे क्योंकि पहले की सीमा अवधि पूर्व-संशोधित परंतुक के तहत आठ साल थी। परंतुक के बाद के भाग का इरादा इस तरह के लंबित आकलनों को सहेजना है और इसलिए एक विशिष्ट तिथि, यानी 31 मार्च, 2002 को शामिल किया गया है। अवधि को आठ वर्ष से घटाकर छह वर्ष करते हुए, 31.3.2002 द्वारा मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन को पूरा करने के लिए समय निर्दिष्ट किया गया है। मूल्यांकन करना एक अत्यंत भौतिक

पहलू है। यदि उक्त तिथि को बचत कारक के रूप में नहीं माना जाता, तो आठ साल की अवधि के लिए लंबित पुनर्मूल्यांकन मामले दायरे में आ जाते और सीमा अवधि में कमी से राजस्व के ब्याज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इसलिए, सुरक्षात्मक प्रावधान। यदि इस तरह का निर्माण नहीं किया जाता है, तो यह असमान होगा, एक तरह से असंगत होगा, क्योंकि एक तरफ सीमा की अवधि कम हो जाती है और एक निर्धारित तिथि तय करने से एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। विधायी उद्देश्य वित्तीय या मूल्यांकन वर्ष की परवाह किए बिना सीमा अवधि को बढ़ाना और बढ़ाना नहीं था। यदि राजस्व के रुख को स्वीकार किया जाना है, तो 2001 के संशोधन का प्रभाव वित्तीय वर्ष के संदर्भ के बिना मामलों को फिर से खोलने को सशक्त और अधिकृत करेगा, बशर्ते कि मूल्यांकन आदेश 31.3.2002 पर या उससे पहले किया गया हो। इस तरह की व्याख्या विधायी इरादे के विपरीत होगी क्योंकि उसी संशोधन ने सीमा अवधि को आठ साल से घटाकर छह साल कर दिया है। तार्किक परिणाम यह है कि विधायी इरादा सीमा अवधि को समाप्त करने और मिटाने का नहीं था, बल्कि "31 मार्च, 2002" की तारीख को केवल उन मामलों की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया था जिन्हें पहले आठ साल की सीमा अवधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। इस प्रकार, 2001 का संशोधन पूरी तरह से पूर्वव्यापी नहीं है, लेकिन यह आंशिक रूप से पूर्वव्यापी है। यदि सीमा अवधि को आठ वर्ष से घटाकर छह वर्ष कर दिया जाए और साथ ही आठ

वर्ष और छह वर्ष के भीतर मामलों के संबंध में राजस्व के हित की रक्षा और सुरक्षा की जाए, बशर्ते कि पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च, 2002 तक पूरा हो जाए। इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि ज्योति ट्रेडर्स (उपरोक्त) में निर्णय अलग करने योग्य है, जो संशोधन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और इसके परिणामस्वरूप, संशोधित प्रावधान पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या गलत है।

20. पूर्वगामी विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत को सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण अलग कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गयी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।